

प्रेषक,

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग- 5

देहरादून: दिनांक 28 अक्टूबर, 2009

विषय: उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों के लिये औषधि क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-5प/1/52/2008-09/33743 दिनांक 27.10.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2008 दिनांक 01.05.2008 से प्रवृत्त होने के कारण शासनादेश सं०-2046(चि०)/206(चि०)/2001 दिनांक 13.09.2001 एवं शासनादेश संख्या 1203/XXVIII(3)-2004-24/2003 दिनांक 15.1.05 के द्वारा चिकित्सालयों/औषधालयों के लिये प्रख्यापित औषधि क्रय नीति सामयिक नहीं रह गयी है। अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2008 के आलोक में राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों के लिये औषधियों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन क्रय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओं से ही किया जायेगा जिसके मूल्यांकन हेतु उनसे चार्टर्ड एकाउण्टेंट (सी०ए०) द्वारा अभिप्रमाणित विगत दो वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट की टर्नओवरकी प्रतियां ली जाए एवं उन्ही फर्मों से दवा की खरीद की जाए जिनका विगत दो वर्षों का टर्नओवर कम से कम 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो। किन्तु उत्तराखण्ड में स्थित स्थानीय उत्पादकों को इस शर्त में छूट देते हुए दो वर्षों का औसतन टर्नओवर 5 करोड़ प्रतिवर्ष होगा।
2. केवल उन्ही फर्मों से औषधियों का क्रय किया जाए जिसके लिए फर्म के पास D.G.Q.A. (रक्षा मंत्रालय) का अनुमोदन/ W.H.O.G.M.P /G.M.P. With Revised Schedule 'M'/G.M.P With G.L.P. का पंजीकरण प्रमाण पत्र हो।
3. निविदा में उल्लिखित औषधियों का निविदा फर्म का अपना उत्पादन व विक्रय दो वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र सी०ए० से प्राप्त कर संबंधित प्रान्त के औषधि नियंत्रक द्वारा प्रमाणित कराकर दिया जाना होगा।
4. किसी भी औषधि निर्माता की वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं वर्ष के वास्तविक उत्पादन में यदि अधिक अंतर हो तो फर्म को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए शासन को इस संबंध में इस शर्त को शिथिल करने का अधिकार होगा।
5. निविदादात्री फर्म अगर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अधोमानक अथवा नकली दवा बनाने में दण्डित हुई हो तो उस ईकाई से औषधि क्रय नहीं किया जाए। यदि फर्म किसी राजकीय संस्था द्वारा क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न करने के दोष में ब्लैक लिस्ट अथवा किसी अपराध में दण्डित हुयी हो तो तब भी फर्म से औषधि का क्रय न किया जाए।
6. प्रत्येक निविदा दात्री फर्म को अपने लाईसेंस की तथा उस पर अनुमोदित सारे औषधि की अद्यतनसूची अपने प्रांत के औषधि नियंत्रक से सत्यापित करानी होगी।
7. कोई भी औषधि डी०पी०सी०ओ० में प्रदत्त सीलिंग प्राइज से अधिक दर पर नहीं क्रय की जायेगी।
8. उत्तराखण्ड के सार्वजनिक उपक्रमों को उक्त शर्त के अतिरिक्त उनके द्वारा उत्पादित की गयी औषधियों से क्रय किये जाने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार मूल्य वरीयता डी०पी० सी०ओ० द्वारा निर्धारित मूल्य के अंतर्गत दी जायेगी।

.....2



अनुभव

अनुभव

अनुभव

9. उत्तराखण्ड की निर्माण इकाईयों के उत्पादों के शासकीय क्रय के संबंध में उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश का अध्यारोही प्रभाव होगा।
10. प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होगी एवं औषधि के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पैकिंग प्रदर्शन पर 'यू०के०जी० सप्लाई', "नॉट फार सेल" इन्डेलिबल इंक से लिखा जाना अनिवार्य होगा।
11. (क) एक बार में क्रय की गयी विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत दवाओं के रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधि के नमूनों की जांच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जांच करायी जाए।
(ख) आपूर्ति की गयी, ऐसी औषधियाँ जो उपयोग के अयोग्य घोषित हों के रखरखाव का उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।
(ग) आपूर्तिकर्ता फर्म के निर्माण एवं विश्लेषण व्यवस्था का निरीक्षण कराये जाने का अधिकार क्रेता सुरक्षित रखेगा।
(घ) यदि आपूर्ति की गयी सामग्री अधोमानक पायी जाती है तो जांच में हुआ व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा ही वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस बिल के अंतर्गत आपूर्तित औषधि की कुल मात्रा की आपूर्ति पुनः की जानी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता आपूर्तिकर्ता फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र होगा।
12. राज्य स्तर पर औषधियों के क्रय हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाना प्रस्तावित है:

राज्य स्तर पर (क) तकनीकी क्रय समिति

1	अपर निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2	अपर निदेशक (चि०उप०), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य
3	वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
4	औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
5	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, द्वारा नामित अन्य तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य
6	संयुक्त निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	संयोजक/सदस्य

(ख) वित्तीय क्रय समिति

1	महानिदेशक/निदेशक(भण्डार), चि०स्वा० एवं प० क०, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2	वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य
3	प्रशासकीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य
4	उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
5	अपर निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य
6	अपर निदेशक (चि०उप०), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य
7	वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
8	औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य

- | | | |
|----|--|--------------|
| 9 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून | सदस्य |
| 10 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून | सदस्य |
| 11 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, दून महिला चिकित्सालय, देहरादून | सदस्य |
| 12 | महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, द्वारा नामित सम्बन्धित चिकित्सकीय विशेषज्ञ | सदस्य |
| 13 | संयुक्त निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय | संयोजक/सदस्य |

(ग) जिला स्तरीय क्रय समिति

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (भण्डार) | संयोजक/सदस्य |
| 3 | उप मुख्य चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| 4 | कोषाधिकारी/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय | सदस्य |
| 6 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय | सदस्य |
| 7 | चीफ फार्मसिस्ट (भण्डार) | सदस्य |

समिति दर अनुबंध, मात्रा अनुबंध व अन्य शर्तों के निर्धारण किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम होगी।

उपरोक्त समितियों के लिए समिति के कुल 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में ही कोरम पूरा माना जायेगा, परन्तु वित्त विभाग के प्रतिनिधि की अनिवार्यता बनी रहेगी।

13. प्रत्येक निविदा खुलने के पश्चात टैक्स ढांचे में परिवर्तन यथा शासनादेश प्रभावी होगा।
14. निविदा प्रपत्र का प्रारूप एवं उसका शुल्क आदि का निर्धारण शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। निविदाओं को आमंत्रित करने के लिए वाइड परिचालन किया जाए तथा निविदा देने की तिथि को ही, निविदा में उल्लिखित शर्तें जैसे स्पेसीफिकेशन, पंजीकरण आदि पूर्ण होना चाहिए।
15. मात्रा अनुबंध व दर अनुबंध की शर्तें समान होगी।
16. नियम 12 पर गठित राज्य स्तरीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर अनुबंध की दरों को शासन द्वारा अनुमोदित कराया जाना होगा। मात्रा अनुबंध के अन्तर्गत औषधि का क्रय, क्रय समिति के अनुमोदन के उपरान्त विभागाध्यक्ष अपने वित्तीय अधिकारों की सीमा तक स्वयं कर सकेंगे तथा उससे अधिक के लिए शासन का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
17. निविदा बाक्स महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। टैक्नीकल तथा फाईनैशियल बिड प्रत्येक फर्म द्वारा दो अलग-अलग लिफाफों में दिये जायेंगे। धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) टैक्नीकल बिड के साथ जमा करनी होगी।
18. प्रत्येक निविदा दात्री फर्म से, निविदा की अनुमानित लागत की धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 के अनुसार होगी, जिसे महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड के नाम रहन किया जाना होगा, देय होगी। सरकार द्वारा निविदा दात्री को बैंक ड्राफ्ट द्वारा दी गयी धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) निविदा के संतोषजनक पूर्ण होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को लौटा दी जायेगी।
19. न्यूनतम दर वाली फर्म से माल की आपूर्ति न होने पर न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत अधिक तक के अन्दर आने वाली फर्म से क्रय किया जाय तथा उच्च दर 10 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसी अवस्था में पुनः निविदाये आमंत्रित की जाय।

20. संविदा में उल्लिखित किसी शर्त के अपूर्ण अथवा उसका उल्लंघन होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा जमः कुल धरोहर राशि (अर्नेश्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।
21. औषधियों के लिए बजट का 60 प्रतिशत परिधिगत अधिकारियों के निस्तारण पर व 40 प्रतिशत महानिदेशक के पास विशेष श्रेणी के औषधियों के क्रय किये जाने हेतु उनके निस्तारण पर रहेगी। परिधिगत अधिकारी अपने उपलब्ध धनराशि का 85 प्रतिशत क्रय अनुमोदित दर अनुबन्ध सूची में करेंगे तथा बाकी का स्थानीय आवश्यकता अनुरूप करेंगे।
22. आपूर्तिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा सुरक्षित गन्तव्य स्थल तक पहुंचने के 60 दिन के भीतर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत गुणवत्ता संबंधी जांच आख्या आने के बाद 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।
23. उत्तराखण्ड दर/मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत (भारत सरकार के उपक्रम सी०पी०एस०यू०ई० की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 102 दवाईयों को छोड़कर) विद्यमान औषधियों के अतिरिक्त अन्य औषधियों को वरीयता क्रम में निम्नानुसार क्रय किया जायेगा :-
1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 3, अक्टूबर 2008 में निहित 102 औषधियों का क्रय निर्धारित दर/न्यूनतम दर पर केन्द्रीय पी०एस०यू०ई० से निहित मार्गदर्शन के अनुरूप किया जा सकेगा।
 2. क्रम संख्या 1 पर अनुपलब्ध औषधियां भारत सरकार के उपक्रम से, जो ई०एस० आई०सी० में उपलब्ध हो की न्यूनतम दर पर क्रय की जायेगी।
 3. क्रम संख्या 2 पर अनुपलब्ध औषधियां ई०एस०आई०सी० के दर अनुबन्ध की न्यूनतम दर पर क्रय की जायेगी।
 4. क्रम संख्या 3 पर अनुपलब्ध औषधियां भारत सरकार के उपक्रम, जो स्वयं औषधि निर्माता हो की न्यूनतम दर पर क्रय की जायेगी।
 5. जिन औषधियों का महानिदेशालय स्तर पर मात्रा अनुबन्ध नहीं किया जा सकेगा उनका क्रय उपरोक्तानुसार ही क्रम संख्या 1, 2, 3 व 4 की वरीयता के क्रम में क्रय की जायेगी।
 6. सर्जिकल सूचर, एक्स-रे फिल्मस, सर्जिकल ग्लब्स, डिस्पोजेबल सीरिज, आई०वी० सैट, गॉजबैंडेज, कॉटन, मैकिनटोस, रबर शीट एवं अन्य सामग्री जो भी डी०जी०एस० एंड डी० पर उपलब्ध हो उसे डी०जी०एस० एंड डी० के दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय की जायेगी।

भवदीय,

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव

संख्या-1284(1)/XXVIII-5-2008-24/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-3/नियोजन विभाग/एन०आई०सी०।
7. गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव